Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- वैज्ञानिकों ने ढूंढी छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियाँ 3
- अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप-महानिदेशक ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को सराहा 6
- रायपुर में तैयार हुआ गाड़ियों के लिये छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमैटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर 7
- छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी नंबर वन 8
- स्वास्थ्य मंत्री ने 'खबरवाद'मासिक पत्रिका का किया विमोचन 9
- नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाज़ार 10
- प्रधानमंत्री ने रायपुर में 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया 11
- खरीफ फसल की सुरक्षा के लिये इस वर्ष भी प्रदेश में चलाया जाएगा 'रोका-छेका अभियान' 13
- मुख्यमंत्री ने गांधी स्टेडियम में नवनिर्मित मल्टीपरपज इंडोर हॉल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सहित विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण तथा शिलान्यास 14
- प्रदेश में 11 से 24 जुलाई तक 'जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा' 15
- 'पौधा तुहर द्वार': वन मंत्री ने हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 16
- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में इस बार कुश्ती एवं रस्सीकूद प्रतियोगिता भी 16
- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध 17
- छत्तीसगढ़ पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान : अब लघु फिल्मों के जरिये जागरूकता के प्रयास 17
- दंतेवाड़ा पहला ज़िला जहाँ मिलेगी वायरोलॉजी लैब की सुविधा 18
- छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 19
- रीपा की सेवा गतिविधियों में आंकांक्षी ज़िला दंतेवाड़ा प्रथम और कांकेर दूसरे स्थान पर 20
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का कांकेर में किया वर्चुअल लोकार्पण 21
- गौठानों में गोबर से 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट उत्पादित 22
- मुख्यमंत्री ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ 22
- छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के हाथों मिला भूमि सम्मान 24
- प्रदेश के दो ज़िला चिकित्सालय और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाज़ा गया 26
- मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ी नाटक 'सुराजी गांव'का विमोचन 26
- विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 6032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित 27
- 'कारवाँ पर्यटन' 29
- मुख्यमंत्री ने 'नवसृजन एक परिचर्चा'के पोस्टर और पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया 30
- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू 31
- रायपुर बनेगा पपीता उत्पादक ज़िला : एक उत्पाद-एक ज़िला योजना में रायपुर शामिल 33
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़-2023 34
- स्टार्ट-अप, स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु स्थापित होंगे 35 इंक्यूबेशन सेंटर 35
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 35
- नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव ज़िले का तीसरा स्थान 36
- हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई व्यावसायिक प्रशिक्षण का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में होगा लागू 37
- मुख्यमंत्री ने मोर बिजली ऐप के नए वर्ज़न 2.0 को किया लॉन्च 38

नोट :

The Vision

छत्तीसगढ़

वैज्ञानिकों ने ढूंढी छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने राज्य में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियों की पहचान की है। ये प्रजातियाँ बहुत ही दुर्लभ हैं व ज्यादातर वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं।

प्रमुख बिंदु

- पौध प्रजातियों को ढूँढने वाली वैज्ञानिकों की टीम में डॉ. एम. एल. नायक, डॉ. राजेंद्र मिश्रा व डॉ. ए. पी. तिवारी शामिल हैं।
- ये प्रजातियाँ घास, बेला, मध्यम वृक्ष एवं झाड़ियो की हैं जिन्हें उदंती अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से खोजी गई हैं।
- डॉ. एम. एल. नायक ने बताया कि पौध प्रजातियों का सैंपल एकत्रित करके हर्वेरियम बनाया गया है। इन प्रजातियों में 1 घास की प्रजाति, 2 बेला की, 2 मध्यम आकार के वृक्ष की और 5 झाड़ियो की प्रजातियाँ शामिल हैं।
- डॉ. नायक ने बताया कि खोजी गई 10 में से 8 प्रजातियाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से व शेष 2 प्रजातियाँ उदंती अभयारण्य से खोजी गई हैं।
- उक्त सर्वे अरुण कुमार पांडेय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के मार्गदर्शन में हुआ।
- उक्त पौध प्रजातियों को देश के जाने-माने जरनल 'द इंडियन फोरेस्टर' ने मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
- वैज्ञानिकों की एक टीम ने जिन पौध प्रजातियों की खोज की है, उनमें शामिल हैं- एलोकेशिया डेसीपियंस, ब्रेयनिया रेटुसा, कोस्मोस्टिग्मा रेसीमोसम, डाइनब्रा पॉलीस्टैचियोस, ड्रैसीना टर्निफ्लोरा, गैम्फोस्टेम्मा परविफ्लोरम, जिमनेमा इनोडोरम, ह्यूबेरेंथा सेरासाइड्स, लेपिसैंथेस टेट्राफिला व सोलेनम इरिंथियम।

लेपिसैंथेस टेट्राफिला

कोस्मोस्टिग्मा रेसीमोसम

नोट :

ड्रैसीना टर्निफ्लोरा

एलोकेशिया डेसीपियंस

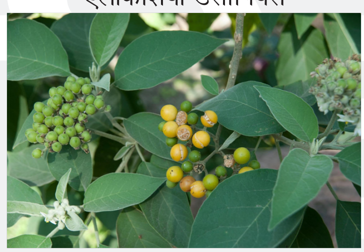

सोलेनम इरिंथियम

ह्यूबेरेंथा सेरासाइड्स

गैम्फोस्टेम्मा परविफ्लोरम

नोट :

ब्रेयनिया रेटुसा

जिमनेमा इनोडोरम

डाइनब्रा पॉलीस्टैचियोस

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप-महानिदेशक ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को सराहा

चर्चा में क्यों?

1 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों (कोदो-कुटकी, रागी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये संचालित 'छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन' के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उप-महानिदेशक (फसल) तथा प्रख्यात कृषि एवं पोषण विशेषज्ञ जोआना केन पोटाका ने की है।

प्रमुख बिंदु

- सुश्री पोटाका ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा किसानों तक बीज वितरण प्रणाली, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के द्वारा मिलेट प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा किसानों से कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पौष्टिकता के मद्देनजर लघु धान्य फसलों का समावेश तथा महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न ज़िलों में मिलेट कैफे की स्थापना एवं संचालन की तारीफ की है।
- सुश्री पोटाका ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के साथ साउथ अफ्रीकन देश घाना में विगत दिनों आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय हाई इम्पैक्ट राईस ब्रीडिंग कार्यशाला' के दौरान हुई मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए इस बारे में ट्वीट किया है। गौरतलब है कि सुश्री पोटाका स्मार्ट फूड कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक भी हैं।
- उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विगत दिनों घाना के कुमासी शहर में आयोजित 'धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण' पर आयोजित चार दिवसीय कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित हुए थे।
- डॉ. चंदेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी दी थी।
- डॉ. चंदेल ने मिलेट मिशन के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लघु धान्य फसलों पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से स्थापित मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर तथा मिलेट कैफे के बारे में भी जानकारी दी थी।
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की दिशा में किये जा रहे अनुसंधान कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

रायपुर में तैयार हुआ गाड़ियों के लिये छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमैटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के फिटनेस की जाँच के लिये रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जाँच की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है।
- मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। परिवहन विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को घर पहुँचाया जा रहा है।
- इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस निरीक्षण के कार्य को भी विभाग ऑटोमैटिक करने जा रहा है।
- इस संबंध में परिवहन सचिव एस.प्रकाश ने बताया कि अब फिटनेस निरीक्षण का कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित मशीन के द्वारा किया जाएगा।
- परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में मशीन के द्वारा रोलर ब्रेक टेस्ट, एक्सल भार टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, साइड स्लिप टेस्ट, जॉइंट प्ले टेस्ट, स्टीयरिंग गियर प्ले टेस्ट, स्पीडो मीटर टेस्ट, स्पीड गवर्नर टेस्ट, एग्जॉस्ट गैस टेस्ट, हेड लाइट टेस्ट किये जाएंगे।
- ट्रांसपोर्ट वाहन को 08 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक 02 वर्ष में फिटनेस प्रमाण निरीक्षण कराना होता है। 08 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसपोर्ट वाहन को प्रत्येक वर्ष फिटनेस निरीक्षण कराना होता है। यह नियम यात्री और माल यान दोनों के लिये होता है, जो कि यात्री या माल ले जाने के लिये कमर्शियल वाहन के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
- पूर्व में फिटनेस निरीक्षण का कार्य आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता रहा है। इंस्पेक्टर द्वारा अनुभव के आधार पर विजुवल इंस्पेक्शन करने के बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति में वाहन-मालिक इस जाँच से संतुष्ट नहीं हो पाते थे।
- अनफिट वाहन यदि रोड में चलते हैं तो उनसे एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। ट्रांसपोर्ट वाहन से एक्सीडेंट होने से जान-माल की हानि ज्यादा होती है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान रखते हुए हैवी गाड़ियों का फिटनेस 01 अप्रैल, 2024 से ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्यत: कराये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।
- राज्य के द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर को गति देने के लिये स्क्रैपिंग नीति भी लाई गई है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग कराने पर नई गाड़ी खरीदने के दौरान टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
- इस छूट का लाभ लेने के लिये पहले गाड़ी को ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर से निरीक्षण कराने के पश्चात् रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैपिंग कराना होगा। स्क्रैपिंग कराने के बाद नयी गाड़ी खरीदने के लिये टैक्स में छूट हेतु सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिया जाएगा जिससे की छूट लाभ मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त यदि 15 वर्ष से अधिक आयु की ट्रांसपोर्ट गाड़ी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के फिटनेस परीक्षण में फेल हो जाती है तो ऐसी गाड़ी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट :

छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने 85.71 फीसदी प्लांट लोड फॅक्टर (पीएलएफ) हासिल कर देशभर के 33 बिजली घरों को पछाड़ कर पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) नई दिल्ली ने 33 स्टेट सेक्टर में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी को बेहतर परफार्मेंस के लिये पहली तिमाही में पहली रैंकिंग दी है।
- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की क्षमता 2840 मेगावाट है, जिसमें 85.71 प्रतिशत पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) के साथ पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर ओडिशा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन है। जिसका प्लांट लोड फैक्टर 84.98 फीसदी रहा है।
- विदित है कि केंद्र सरकार का उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) नई दिल्ली हर तीन महीने में रैंकिंग जारी करता है।
- देशभर के 33 स्टेट सेक्टर में औसत पीएलएफ 66.97 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ के संयंत्रों ने 85.71 प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया है। पूरे भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों का औसत पीएलएफ 70.02 प्रतिशत रहा। यानी सभी संयंत्रों से अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के संयंत्रों में हुआ।
- जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने बताया, अप्रैल-मई-जून के उत्पादन के आधार पर रैंकिंग मिली है। इस दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति थी। सभी राज्यों में बिजली की बहुत अधिक मांग थी। छत्तीसगढ़ में 18 अप्रैल को बिजली की मांग 5878 मेगावाट तक पहुँच गई थी।
- ऐसी परिस्थिति में जनरेशन कंपनी के संयंत्रों ने लगातार बिना रूके कार्य किया और प्रदेश में बिना पॉवर कट के निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी रखी। खासकर इस वर्ष हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र (डीएसपीएम) कोरबा पूर्व तथा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा ने बेहतर उत्पादन किया है।
- 1984 में स्थापित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के यूनिट क्रमांक 04 ने 162 दिन 12 घंटे बिना थमे विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है, पहले इस यूनिट से अधिकतम 111 दिन 9 घंटे तक ही लगातार विद्युत उत्पादन हुआ था।

नोट :

स्वास्थ्य मंत्री ने 'खबरवाद' मासिक पत्रिका का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में मासिक पत्रिका 'खबरवाद' के पहले अंक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उम्मीद जताई कि इस नई पत्रिका के माध्यम से प्रदेश के लोगों को सम-सामयिक घटनाओं के साथ ही यहाँ के राज-काज की ताजा जानकारी भी मिलेगी।
- 'खबरवाद' के संपादक श्रीकांत बाघमारे ने पत्रिका के विमोचन के अवसर पर कहा कि राज्य की प्रमुख खबरों के सटीक विश्लेषण, बुद्धिजीवियों के विचार, राजनीति, शासन, प्रशासन के साथ ही यहाँ की योजनाओं व जनहित के मुद्दों से जुड़े समाचार इसमें प्रमुखता से प्रकाशित किये जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि 'खबरवाद डॉट कॉम' के साथ ही अब पत्रिका के माध्यम से भी लोगों को प्रदेश की खबरों से रू-ब-रू कराया जाएगा।

नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाज़ार

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाज़ार विकसित होगा। लगभग 438.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- नवा रायपुर में बनने वाले देश के सबसे बड़े थोक बाज़ार का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा किया जाएगा। यहाँ छोटे-बड़े सभी व्यापारियों के लिये आधारभूत ज़रूरी सुविधाएँ होंगी।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाज़ार की कार्ययोजना को इस तरह से अमलीजामा पहनाएँ ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाज़ार छोटे-बड़े सभी व्यापारियों की ज़रूरत पूरा कर सके और यहाँ व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में नागरिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने 'मितान योजना' के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की डिलीवरी बिना कार्यालय पहुँचे तथा शीघ्रता से नागरिकों को मिल पा रही है।
- गौरतलब है कि 'मितान योजना' पहले राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में किया गया है।
- बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन बच्चों के आधार-कार्ड से संबंधित हैं। 'मितान योजना' अंतर्गत अब तक प्रदेश के नगर निगमों के 1 लाख 03 हज़ार 315 हितग्राहियों के विभिन्न दस्तावेज़ तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है।
- बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिये मितान को सबसे अधिक फोन आते हैं और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही जाति और आय प्रमाणपत्र भी काफी बने हैं। अधिकारियों ने बताया कि फोन कॉल के साथ ही एप के माध्यम से मितान योजना की सेवा शीघ्र ही दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कहा धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स बेहतर लोकेशन में खोले जाएँ। उन्होंने इस मौके पर 'स्लम स्वास्थ्य योजना' की समीक्षा की और लगातार हेल्थ कैंप आयोजित करने के निर्देश दिये।
- बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक 132 करोड़ रुपए की बचत हितग्राहियों को हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन मेडिकल स्टोरों का लोकेशन भी बेहतर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में एसएमएस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जानकारी दिये जाने के प्रयासों पर काम हो रहा है।
- मुख्यमंत्री ने 'महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा)' की समीक्षा में कहा कि सभी उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति की व्यवस्था हो, सी-मार्ट में इनकी उपलब्धता हो।
- उन्होंने कहा कि रीपा में अनेकों तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। बेकरी एवं खाद्य उत्पाद, मिलेट, परिधान, निर्माण आदि क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और उद्यमी आगे आ रहे हैं। शासकीय भवनों में रंग-रोगन के लिये गोबर पेंट का उपयोग हो रहा है। निजी क्षेत्रों में भी इसकी बिक्री बढ़ाई जाए।
- रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाई-फाई से डिजिटल कनेक्टीविटी अच्छी होने के कारण युवा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वाई-फाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है।
- इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि संभाग स्तरीय मिलेट कार्निवाल के लिये योजना तैयार हो रही है। गोबर पेंट के उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिये जा रहे हैं। चूँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का संस्था से अनुबंध है, अतएव तकनीकी सहायता वहाँ से भी मिल सकेगी।

नोट :

प्रधानमंत्री ने रायपुर में 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 7500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने आज लगभग 6,400 करोड़ रुपए की पाँच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
- राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली परियोजनाओं में जबलपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोडेबोड़ खंड की 33 किमी. लंबा 4 लेन मार्ग शामिल है।
  - पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यह खंड जगदलपुर के पास इस्पात संयंत्रों के कच्चे माल, तैयार उत्पादों की आवाजाही के लिये महत्त्वपूर्ण है और लौह अयस्क-समृद्ध क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री ने एनएच-130 के बिलासपुर से अंबिकापुर खंड के 53 किमी. लंबे 4-लेन बिलासपुर-पथरापाली खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया।
  - यह उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा और आसपास के क्षेत्रों में कोयला खदानों को कनेक्टिविटी प्रदान करके कोयले की आवाजाही को बढ़ावा देगा।
- प्रधानमंत्री ने 6-लेन ग्रीनफील्ड रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
  - इनमें एनएच 130 सीडी पर 43 किमी. लंबे छह लेन वाले झांकी-सरगी खंड; एनएच 130 सीडी पर 57 किमी. लंबा छह लेन वाला सरगी-बसनवाही खंड; और एनएच-130 सीडी का 25 किमी. लंबा छह लेन वाला बसनवाही-मारंगपुरी खंड शामिल है।
  - इसके अलावा इस परियोजना का एक प्रमुख घटक 2.8 किमी. लंबी 6-लेन सुरंग है, जिसमें उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अप्रतिबंधित वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के लिये 27 पशुओं के निकासी मार्ग और बंदरों के लिये 17 छतरियाँ शामिल हैं।
  - इन परियोजनाओं से धमतरी में चावल मिलों और कांकेर में बॉक्साइट समृद्ध क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और कोंडागाँव में हस्तशिल्प उद्योग को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर ये परियोजनाएँ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रमुखता देंगी।

- प्रधानमंत्री ने 750 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 103 किमी. लंबी रायपुर-खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इससे छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिये बंदरगाहों से कोयला, इस्पात, उर्वरक और अन्य वस्तुओं का परिवहन आसान हो जाएगा।
- उन्होंने 290 करोड़ रुपए की लागत से विकसित केवटी-अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किमी. लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। नई रेलवे लाइन भिलाई इस्पात संयंत्र को दल्ली-राजहरा और रावघाट क्षेत्रों की लौह अयस्क खदानों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और घने जंगलों से गुजरते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों को जोड़ेगी।
- प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60 हज़ार मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया।
- उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से अंतागढ़-रायपुर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया।
- प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दो आर्थिक गलियारों रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारा और रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा का शिलान्यास किया।
- इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएँ लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ के धान किसानों, खनिज उद्योग और पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा।
- इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री टी एस सिंह देव, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के साथ-साथ संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य भी उपस्थित थे।

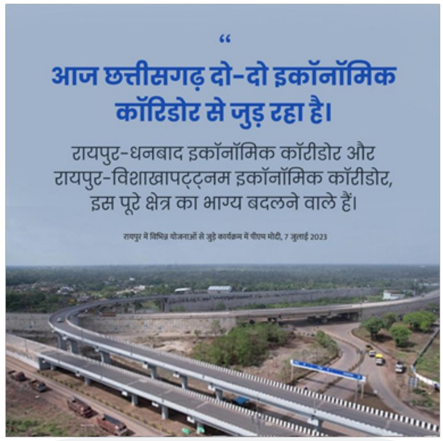

खरीफ फसल की सुरक्षा के लिये इस वर्ष भी प्रदेश में चलाया जाएगा 'रोका-छेका अभियान'

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2023 को राज्य में खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण और उनसे खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों और ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गाँवों में 17 जुलाई तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप 'रोका-छेका अभियान' चलाने के दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोका-छेका प्रथा के अनुसार व्यवस्था की सुनिश्चितता की जाए। इसके लिये ग्राम स्तर पर 17 जुलाई तक स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप रोका-छेका अभियान चलाकर सभा आयोजित की जाए। साथ ही सभी निर्मित गौठानों में 30 जुलाई से पहले चारागाह की स्थापना की जाए। जहाँ चारा उत्पादन हो।
- अधिकारियों को रोका-छेका अभियान के तहत ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें 'रोका छेका' प्रथा के अनुरूप पशुओं से फसल बचाव का निर्णय ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों के द्वारा लिया जाएगा।
- फसल को चराई से बचाने हेतु पशुओं को गौठान में नियमित रूप से लाये जाने के संबध में प्रत्येक गौठान ग्राम में मुनादी कराने और गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के निर्देश भी दिये गए हैं।
- जारी निर्देश में 'रोका छेका' प्रथा के अंतर्गत गौठानों में पशुओं के प्रबंधन व रखरखाव की उचित व्यवस्था हेतु गौठान प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने को भी कहा गया है। ऐसे गौठान जो सक्रिय परिलक्षित नहीं हो रहे हों, वहाँ आवश्यकतानुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति में संशोधन कर सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण और उनसे खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिये इस वर्ष भी रोका-छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। रोका-छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी पंरपरा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इसे अभियान के रूप में राज्य में शुरू किया गया है, जिसके बड़े ही उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू वर्ष के दौरान यह अभियान पुन: चलाया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण के लिये 'रोका छेका' प्रथा प्रचलित है, जिसमें फसल बुआई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाली हानि से बचाने के लिये पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशुओं को बांधकर रखने पहटिया (चरवाहा) की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। इस प्रयास से न सिर्फ किसान जल्दी बुआई का काम कर पाते हैं, बल्कि दूसरी फसल लेने हेतु भी प्रेरित होते हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री ने गांधी स्टेडियम में नवनिर्मित मल्टीपरपज इंडोर हॉल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सहित विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण तथा शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

8 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी स्टेडियम के अंतर्गत स्थित खेलो इंडिया मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम हॉल सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यहाँ 4 करोड़ 37 लाख 64 हज़ार रुपए की लागत से निर्मित इस सर्वसुविधायुक्त मल्टीपरपज इंडोर हॉल का लोकार्पण किया। यहाँ खिलाड़ियों हेतु 04 बैडमिंटन कोर्ट, 03 टेबल टेनिस, बास्केट बॉल एवं बॉलीबॉल कोर्ट की सुविधा है।
- मल्टीपरपज इंडोर हॉल में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों हेतु पृथक्-पृथक् चेंजिंग रूम, वॉशरूम, क्लॉक रूम, खेल उपकरण कक्ष, प्रथम तल में सीटिंग एरिया उपलब्ध है। यहाँ भविष्य हेतु स्क्वैश कोर्ट, शूटिंग रेंज इत्यादि की भी योजना है।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केशवपुर, सोहगा, राजापुर, बिलासपुर तथा निम्हा में 6 करोड़ 86 लाख 11 हज़ार की लागत से निर्मित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। वहीं 5 करोड़ 39 लाख 47 हज़ार रुपए की लागत के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

प्रदेश में 11 से 24 जुलाई तक 'जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा'

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक 'जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा (परिवार नियोजन पखवाड़ा)' चलाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान ग्राम स्तर से लेकर ज़िला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर पुरूष एवं महिला नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता व भ्रांतियों को दूर किया जाएगा।
- पखवाड़े के दौरान ए.एन.एम. और मितानिनें घर-घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों के बारे बताएंगी। हितग्राहियों को जरूरी परामर्श और परिवार नियोजन की सेवाएँ भी इस दौरान प्रदान की जाएंगी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परिवार कल्याण के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर ने बताया कि सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इनमें पुरूष एवं महिला नसबंदी, निरोध, गर्भ निरोधक गोली, इंजेक्शन, कॉपर-टी जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
- डॉ. टोंडर ने बताया कि सभी ज़िला चिकित्सालयों, चिन्हांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में एन.एस.व्ही. की सुविधा उपलब्ध है।
- शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में नसबंदी के बाद पुरूष हितग्राहियों को तीन हज़ार रुपए और महिला हितग्राहियों को दो हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

नोट :

‘पौधा तुहर द्वार’: वन मंत्री ने हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ‘पौधा तुहर द्वार’योजना के तहत राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे दो हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छ वातावरण तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा ‘पौधा तुहर द्वार’की योजना के तहत राज्य भर में पौध वितरण का कार्य जारी है।
- वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए ‘पौधा तुहर द्वार’योजना के तहत रायपुर नगर निगम अंतर्गत घर तक नि:शुल्क पौधा पहुँचाकर दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि यह योजना लगभग डेढ़ माह तक चलेगी, जिसमें आंवला, करंज, नीम, गुलमोहर, जामुन, मुनगा, कचनार, अमरूद, सीताफल, पेल्टाफार्म, नींबू, बादाम आदि प्रजाति के पौधों को आम जनों को मांग के अनुसार उपलब्ध पौधों को घर दुकान, आफिस, फैक्ट्री आदि स्थल पर पहुँचाकर वृक्षारोपण करने हेतु नि:शुल्क पौधा प्रदाय किया जाएगा।
- गौरतलब है कि विगत वर्ष में ‘पौधा तुहर द्वार’योजना के तहत 92 स्थलों में 2164 हितग्राहियों को 10207 पौधे जाम, आँवला, नींबू, सीताफल, कटहल, बेल, जामुन, नीम, कचनार, गुलमोहर एवं मुनगा आदि पौधों का वितरण किया गया था एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत शासकीय/अर्द्ध-शासकीय, नगर निगम, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य हितग्राहियों को 571974 पौधों का नि:शुल्क वितरण भी किया गया था।
- मनरेगा योजना अंतर्गत इस वर्ष 29 शासकीय/अर्द्ध-शासकीय, शिक्षण संस्था एवं अन्य हितग्राहियों को कुल 135965 पौधों का मांग के अनुसार नि:शुल्क वितरण किया गया है।
- इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा रायपुर नगर निगम क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आम जनों को पौधा उपलब्ध कराकर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में इस बार कुश्ती एवं रस्सीकूद प्रतियोगिता भी

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष शुरू की गई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को मिली लोकप्रियता को देखते हुए इस बार हरेली तिहार के दिन शुरू होने वाली छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 को और भी रोमांचक बनाने के लिये एकल श्रेणी में दो नए खेल रस्सीकूद एवं कुश्ती को भी शामिल किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में इस बार 16 तरह की खेलों में स्पर्धाएँ आयोजित होंगी, जिसमें दलीय एवं एकल श्रेणी में छत्तीसगढ़िया लोक-संस्कृति में रचे-बसे 8-8 तरह के खेलों को शामिल किया गया है।
- लगभग 2 महीने 10 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इन खेलों के लिये नियमावली बनाई गई है। इस खेल की समय-सीमा 15 मिनट रखी गई है। मैदान का आकार 6 बाई 6 फीट होगा। निर्णायकों की संख्या 03 होगी।
- कुश्ती खेल में महिला एवं पुरूष वर्ग में अलग-अलग 5 वेट केटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें महिला वर्ग में 40 किलोग्राम तक, 41 से 50 किलोग्राम तक, 51 से 60 किलोग्राम तक, 61 से 70 किलोग्राम तक एवं 70 किलोग्राम से ऊपर तक की वेट केटेगरी रखी गई है।
- इसी तरह पुरूष वर्ग में 50 किलोग्राम तक, 51 से 60 किलोग्राम तक, 61 से 70 किलोग्राम तक, 71 से 80 किलोग्राम तक एवं 80 किलोग्राम से ऊपर तक की वेट केटेगरी निर्धारित की गई है।
- कुश्ती प्रतियोगिता के लिये बनाए गए नियानुसार मैच 03 मिनट के दो अंतराल में होगा एवं प्रत्येक अंतराल में 30 सेकंड का विराम मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के नियम, फाउल भारतीय कुश्ती संघ के अनुरूप होंगे। इसमें निर्णायकों की संख्या 06 होगी। निर्णायकों द्वारा नियमानुसार घोषित खिलाड़ी विजेता माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह कदम उठाया है।
- राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार 'लोक स्वास्थ्य' (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान : अब लघु फिल्मों के जरिये जागरूकता के प्रयास

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब लघु फिल्मों के जरिये भी जन-जागरूकता के प्रयास किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के रचनाधर्मी लोगों को सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म बनाने के लिये प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं।
- प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये ऑनलाइन पंजीयन 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2023 निर्धारित है। लुघ फिल्म प्रविष्टियों के लिये विस्तृत नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

नोट :

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ पूरे देश में सड़क सहयोग में वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- फिल्म का श्रेणी निर्धारण किया गया है। फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंड़ी, हल्बी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुडुख, सादरी बैगानी, कमारी, ओरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोंडी, भुजिया आदि में हिन्दी भाषांतर, उच्चारण के साथ होना चाहिये। किसी भी भारतीय भाषा में हिन्दी भाषांतर, उच्चारण, सबटाइटल के साथ होना चाहिये।
- फिल्म की अविधि 2 मिनट निर्धारित की गई है। मूल फिल्म पूर्ण HD (1920'1080) प्रारूप या उससे ऊपर की हो सकती है। गलत/अपर्याप्त अस्पष्ट, अपूर्ण विवरण वाले प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार चयन के लिये जमा की गई फिल्म को अंतिम माना जाएगा और जमा करने के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इन लघु फिल्मों को अलग-अलग केटेगरी में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा-
  - सर्वश्रेष्ठ फिल्म - 80,000 रुपए
  - सर्वश्रेष्ठ कहानी - 25,000 रुपए
  - सर्वश्रेष्ठ सिनेमॅटोग्राफी - 25,000 रुपए
  - सर्वश्रेष्ठ अभिनेता/अभिनेत्री - 25,000 रुपए

दंतेवाड़ा पहला ज़िला जहाँ मिलेगी वायरोलॉजी लैब की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा ऐसा पहला ज़िला चिकित्सालय होगा जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वायरोलॉजी लैब के स्थापना के पश्चात् ज़िला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस बी एवं सी की जाँच की जाएगी।
- पहले हेपेटाइटिस जाँच के पश्चात् मरीजों का रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव होने पर आगे की जाँच के लिये एम्स भेजा जाता था। जहाँ रिपोर्ट आने में माह भर का समय लग जाता था। निजी लैब संस्थानों में यह जाँच कराने में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए की राशि खर्च हो जाती थी।
- अब दंतेवाड़ा ज़िला चिकित्सालय के वायरोलॉजी लैब में यह जाँच नि:शुल्क की जाएगी, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा और महीने भर का इंतेजार भी नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी।
- इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री के घोषणानुसार ज़िला चिकित्सालय में सिटीस्केन की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ दूर-दूर के ग्रामीणजन उठा रहे हैं। अब इसके लिये जगदलपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, स्व-रोजगार के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद ने प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिये उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई है।
- राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019' को समावेशित करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

रीपा की सेवा गतिविधियों में आंकांक्षी ज़िला दंतेवाड़ा प्रथम और कांकेर दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की रीपा की सेवा गतिविधियों में राज्य के आकांक्षी ज़िला दंतेवाड़ा प्रथम और कांकेर द्वितीय स्थान पर हैं।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ सरकार की रीपा योजना वास्तव में 'सुराजी गाँव योजना' के तहत गाँवों में निर्मित गौठान में संचालित आयमूलक गतिविधियाँ का प्रमुख केंद्र है। रीपा केंद्रों में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
- गौठानों में रीपा के माध्यम से आयमूलक गतिविधियों के संचालन के लिये शासन द्वारा आधारभूत संरचनाएँ एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों को स्व-रोज़गार की गतिविधियों के संचालन में मदद मिल रही है।
- रीपा में काम करने के पूर्व उद्यमियों को शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रीपा केंद्रों में संचालित गतिविधियों का सतत् निरीक्षण भी किया जा रहा है।
- विदित हो कि राज्य के विभिन्न गौठानों में कुल 300 रीपा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इन रीपा केंद्रों में 5849 महिलाएँ और 4107 पुरुष आजीविका गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं।
- राज्य शासन द्वारा इन रीपा केंद्रों में 1546 गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें से 1103 गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। जून की स्थिति में 213 रीपा केंद्रों में सेवा गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।
- इन सेवा गतिविधियों में आधार केंद्र, बीसी सखी, कंप्यूटर, कूलर और मोटर वाहन रिपेयर, रेस्टोरेंट, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग मशीन, पेयजल, टेंट एवं कैटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना से गाँवों में ग्रामीणों को रोज़गार व स्व-रोज़गार मिलने लगा है। गाँवों को उत्पादन का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का कांकेर में किया वर्चुअल लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से कांकेर में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंगेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे, वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में आगे भी इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
- विदित है कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हीं में से प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कांकेर में हुआ।
- मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कांकेर ज़िले में आयोजित इस कार्यक्रम में कांकेर के स्कूली बच्चों के लिये संचालित 'हमर लक्ष्य'कार्यक्रम अंतर्गत एनआईटी रायपुर में चयनित तीन छात्राओं तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में चयनित एक छात्रा से बातचीत की।
- गौरतलब है कि कांकेर ज़िले में स्कूली बच्चों के लिये संचालित 'हमर लक्ष्य'कार्यक्रम के अंतर्गत तहत ज़िले के 75 बच्चों ने जेईई में क्वालीफाई किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के विद्यार्थी को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिये वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई। यह योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुई।
- प्रदेश में आज स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिन्दी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हो रहे हैं। बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत अब तक तीन किश्तों में 01 लाख 17 हज़ार हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।
- कांकेर ज़िला कलेक्टर कांकेर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि बेरोज़गारी भत्ता योजना के जिन हितग्राहियों को हैदराबाद में प्लेसमेंट मिला है, उन्हें 13 से 15 हज़ार रुपए प्रतिमाह आय प्राप्त होगी। इस योजना से ज़िले के 112 हितग्राहियों को अब तक नौकरी मिल चुकी है।

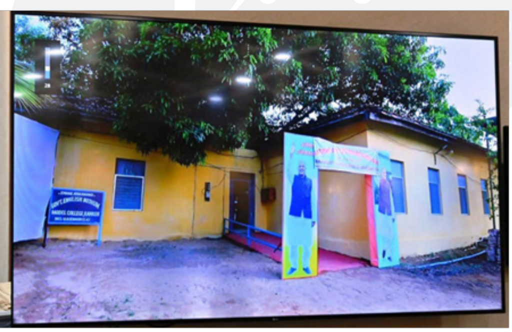

गौठानों में गोबर से 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट उत्पादित

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है।
- क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 2,10,843 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 4 करोड़ 34 लाख 79 हज़ार रुपए की आय हुई है।
- राज्य में फिलहाल 64 प्राकृतिक पेंट की इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 51 यूनिट स्थापित हो चुकी है, जबकि 47 इकाईयों में पेंट उत्पादन किया जा रहा है। निर्माणाधीन 13 पेंट यूनिटों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है।
- 'गोधन न्याय योजना' के तहत गौठानों में गोबर खरीदी के साथ-साथ 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है।
- गौठानों में अब तक 8 लाख 57 हज़ार 88 रुपए में 2 लाख 14 हज़ार 272 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 91,630 लीटर कीट नियंत्रक 'ब्रम्हास्त्र' और 34,590 लीटर वृद्धिवर्धक 'जीवामृत' का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका विक्रय किया जा रहा है।
- इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 88,227 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और 32,765 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय कर खेती में उपयोग किया गया है।

मुख्यमंत्री ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

17 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के ग्राम पंचायत नवागाँव में 'हरेली पर्व'के अवसर पर गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित 'हरेली' कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर 'बछरू'को लॉन्च किया। 36 नंबर की जर्सी और गले में सोहई की माला पहने बछरू छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पहचान बनने के साथ-साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहा है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का ये दूसरा वर्ष है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इस वर्ष पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती जैसे खेल भी इसमें शामिल किये गए हैं। इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 16 पारंपरिक मुकाबलों के साथ 6 चरणों में संपन्न होगी।
- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में तीन अलग-अलग आयु वर्ग में 30 लाख से ज्यादा महिला एवं पुरूष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

- छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएँ दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएँ शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भँवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर प्रतियोगिता 17 जुलाई से शुरू हुआ जो 22 जुलाई तक नॉकआउट पद्धति से चलेगा
- वहीं दूसरा स्तर ज़ोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब बनाया जाएगा। इसका आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। विकासखंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर का आयोजन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा।
- ज़िला स्तर का आयोजन 25 अगस्त से 04 सितंबर तक होगा। संभाग स्तर का आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा और अंत में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी, जिसका आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा।
- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बाँटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा वर्ग 18-40 वर्ष आयु सीमा तक और तीसरे वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी भाग ले सकेंगे।
- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर प्रथम आने वाले विजेता खिलाड़ियों को 1000 रुपए, द्वितीय स्थान पर 750 रुपए एवं तीसरा स्थान के लिये 500 रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।
- इसी तरह ज़िला स्तर पर प्रथम आने वाल विजेता प्रतिभागियों को 2000 रुपए की राशि, द्वितीय आने पर 1500 रुपए और तीसरे स्थान के लिये 1000 रुपए की राशि सहित प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।
- संभाग स्तर पर विजेता प्रतियोगियों को प्रथम आने पर 3000 रुपए, द्वितीय आने पर 2500 रुपए एवं तीसरे स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को 2000 रुपए एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।
- राज्य स्तर पर ओलंपिक के अंतिम आयोजन में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 5000 रुपए, द्वितीय आने पर 4500 रुपए एवं तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 4000 रुपए की राशि और प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।
- विदित है कि पिछले बार के ओलंपिक में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। गाँव-गाँव में पारंपरिक खेलों के प्रति एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ।
- उल्लेखनीय है कि लोक संस्कृति से जुड़े छत्तीसगढ़ का पहला तिहार (त्यौहार) हरेली है, जिसे प्रदेश भर में बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी के उपयोग में आने वाली कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हरेली में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गेड़ी का आनंद लेते हैं।

नोट :

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के हाथों मिला भूमि सम्मान

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाज़ा गया। इसके साथ ही प्रदेश के दो ज़िलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिये भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के मौजूदा चार घटकों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रदेश और दो ज़िलों को यह सम्मान मिला है।
- समारोह में राज्य स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और प्रबंधन के लिये सचिव राजस्व विभाग नीलम नामदेव एक्का, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक किरण कौशल, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा ने राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान प्राप्त किया।
- इसी प्रकार ज़िला स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और प्रबंधन के लिये बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा और सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
- गौरतलब है कि डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े चार घटकों लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय का तहसील कार्यालय से समन्वय, मॉर्डन रिकॉर्ड रूम तथा सर्वे-रिसर्वे का कार्य प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा ज़िले में शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं। ये ज़िले भूमि प्रबंधन में देश के शीर्ष ज़िलों में शामिल हैं।
- भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन से लोगों को अपनी ज़मीन से जुड़ी जानकारियाँ रियल-टाइम पर उपलब्ध हो रही हैं। इस जानकारी को मोबाइल से कहीं से भी और किसी भी वक्त इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और इसके प्रबंधन से भूमि संबंधी जानकारी अब लोगों की आसान पहुँच में है। लोगों को भूमि संबंधी अभिलेख प्राप्त करने के लिये शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।
- लोगों को आसानी से सभी अभिलेख मिलने से ज़मीन से जुड़े धोखा-धड़ी के मामले में भी कमी आई है। भूमि संबंधी न्यायालयों में मुकदमे भी कम हुए हैं। भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण से ऐसे प्रमाण-पत्र, जिनमें भू-अभिलेखों की जानकारी की आवश्यकता होती है, उन प्रमाण पत्रों के लिये आसानी से दस्तावेज़ उपलब्ध हुए हैं। इससे लोगों को आसानी से आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र मिल रहा है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य नागरिक को राईट ऑफ रिकॉर्ड (रिकॉर्ड का अधिकार) भी सुनिश्चित करना है।

नोट :

प्रदेश के दो ज़िला चिकित्सालय और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाज़ा गया

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर ज़िला चिकित्सालय, बलरामपुर ज़िला चिकित्सालय तथा कोरबा ज़िले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाज़ा है।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार ने बस्तर ज़िला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (National Quality Assurance Standard), लक्ष्य (LaQshya) और मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं बलरामपुर ज़िला अस्पताल और करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एनक्यूएस तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन किया गया है।
- सुदूर वनांचलों में स्थित शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी क्षेत्रों तक पहुँच रही हैं।
- विदित है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इस साल मार्च से जून के बीच इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने बस्तर ज़िला चिकित्सालय के मूल्यांकन के बाद 12 विभागों को एनक्यूएस, लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी सेवाओं के लिये लक्ष्य कार्यक्रम के तहत तथा पीडियाट्रिक एवं एसएनसीयू के लिये मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
- करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी सात विभागों को एनक्यूएस तथा लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी के लिये लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएँ, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इंफेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ी नाटक 'सुराजी गांव' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में दुर्गा प्रसाद पारकर की नाट्य रचना 'सुराजी गांव' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री को दुर्गा प्रसाद पारकर ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ी नाटक राज्य सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना 'नरवा, गरूवा घुरूवा, बाड़ी' पर आधारित है। उन्होंने इस नाटक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही योजना नरवा, गरूवा घुरूवा, बाड़ी से ग्रामीणों के जीवन में आ रहे बदलाव को रेखांकित किया है।
- 'सुराजी गांव' रचना के माध्यम से उनका प्रयास राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना के विषय में लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्द्धन, मृदा स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन को आमजन की सहभागिता से सफल बनाने के लिये 'सुराजी गांव योजना' 2 अक्तूबर, 2019 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत नरवा (बरसाती नाले), गरवा (पशुधन), घुरवा (कंपोस्ट खाद निर्माण) और बाड़ी (सब्जी और फलोद्यान) के संरक्षण एवं संवर्द्धन का अभियान प्रारंभ किया गया है।

नोट :

- नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के लगभग 29000 बरसाती नालों को चिन्हित कर उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इससे वर्षाजल का संरक्षण होने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों का भू-जलस्तर सुधर रहा है। नालों के जरिये ग्रामीणों को कृषि के लिये सिंचाई का पानी मिल रहा, मवेशियों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल रही, साथ ही गर्मी के दिनों में भी ग्रामीणों को निस्तारी के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वन्य प्राणियों के लिये भी गर्मी के दिनों में पेयजल की किल्लत नहीं होती और उनके लिये हर वक्त पानी मिल रहा है।
- गरवा कार्यक्रम के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये गाँवों में गौठान बनाकर वहाँ पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई हैं। गौठानों में पशुओं के लिये डे-केयर की व्यवस्था है। इसके तहत चारे और पानी का नि:शुल्क प्रबंध किया गया है। इससे मवेशियों को चारे के लिये भी भटकना नहीं पड़ रहा है।
- घुरवा कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन कर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- बारी कार्यक्रम- छत्तीसगढ़ में बाड़ी को बारी कहा जाता है। ग्रामीणों के घरों से लगी भूमि में 3 लाख से अधिक व्यक्तिगत बाड़ियों को विकसित किया गया है। साथ ही गौठानो में बनाई गई करीब 4429 सामुदायिक बाड़ियों के जरिये फल, साग-सब्जियों के उत्पादन से कृषकों को आमदनी के साथ-साथ पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के जरिये ग्रामों और बसाहटों में बाड़ियों को विकसित कर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

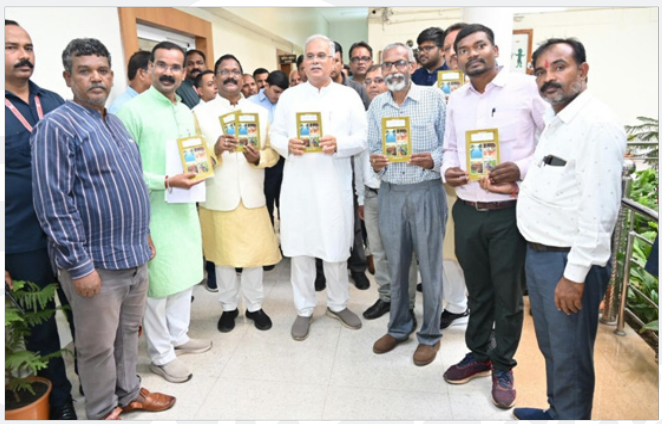

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 6032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 6031 करोड़ 75 लाख 2 हज़ार 977 रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हज़ार 532 करोड़ रुपए हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है।
- पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हज़ार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हज़ार 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष शुरूआती दिनों में कम वर्षा ने चिंता बढ़ाई थी, किंतु अब अच्छी बारिश हो रही है, जिससे इस वर्ष अच्छी फसल की पूरी संभावना है। पिछले कुछ वर्ष में अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 प्रतिशत जलभराव हो चुका है।

- उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है।
- सुगम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लिये 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन दुकान के संचालक के लिये 95 करोड़ रुपए, सुपोषण अभियान के अंतर्गत फोर्टिफाईड चावल के वितरण के लिये 76 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के विकास के लिये अनुपूरक बजट में प्रावधान किये गए है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के विकास के लिये अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।
- अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2000 करोड़ रुपए की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ-
  - प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महँगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोतरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हज़ार रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।
  - 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  - 10 हज़ार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं 05 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
  - शासकीय सेवकों के लिये उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
- सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने के लिये राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नोट :

'कारवाँ पर्यटन'

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कारवाँ गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर कारवाँ के पृथक् से पंजीयन हेतु टैक्स दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कारवाँ गाड़ी के पंजीयन के लिये गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा नये-नये कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिल स्टेशनों, जंगलों और विरासत स्थलों पर 'कारवाँ पर्यटन'को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
- कारवाँ पर्यटन की अवधारणा ने दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है। इस नीति के तहत मनोरंजक वाहन या घूमने के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहन, टूरिस्ट वैन या मोटर घरों को उन स्थानों पर अनुमति दी जाएगी, जहाँ स्थायी निर्माण निषिद्ध है और जहाँ होटल और रिसॉर्ट दुर्लभ हैं।
- इसका उद्देश्य सुरक्षित यात्रा प्रदान करना और टूर ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना है। यह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य आकर्षणों का आनंद लेने की पर्यटकों को अनुमति देगा और इससे पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।
- क्या है मोटर कारवाँ?
  - कारवाँ एक तरह का यात्री वाहन है, जिसे विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है। इस वाहन में बैठने और सोने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ टेबल और किचन भी होता है, कई वाहनों में बाथरूम भी होता है। एक तरह से मोटर कारवाँ एक चलता-फिरता होटल या घर के समान होता है।
  - कारवाँ वाहन बनाने के लिये कोई नई गाड़ी या केवल चेसिस खरीदकर उसे पंजीकृत बॉडी बिल्डर से कारवाँ वाहन बनवाया जा सकता है अथवा फिर कोई पुरानी गाड़ी को भी मॉडिफाई कर कारवाँ वाहन बनवाया जा सकता है, लेकिन कारवाँ गाड़ी बनाने के लिये पुरानी गाड़ी तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये।
  - यह टूरिस्ट सर्किट, गंतव्यों में भी परिवार-उन्मुख पर्यटन को बढ़ावा देता है, जहाँ पर पर्याप्त होटल आवास नहीं होते हैं।
  - यात्रा, अवकाश और आवास के उद्देश्य से मोटर कारवाँ का उपयोग किया जा सकता है। एडवेंचर टूरिज़्म के लिये भी मोटर कारवाँ का काफी उपयोग किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ में विशाल भूमि क्षेत्र और परिदृश्य हैं, जो मोटर कारवाँ पर्यटन के लिये एक नया पहलू जोड़ेगा। वर्तमान में ईको, वन्यजीव, तीर्थ पर्यटन इत्यादि की मांग बढ़ रही है। इसमें दूर-दराज के इलाकों, जंगलों और नदियों में जाना और रहना शामिल है।
- पर्यटन स्थलों पर पहले से ही आवास की कमी है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में और कुछ स्थानों पर जहाँ स्थायी निर्माण न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही संभव है। ऐसे परिदृश्य में कारवाँ टूरिज़्म प्रभावी रूप से बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्वालिटी, स्टैंडर्ड और सुरक्षा मानदंडों का भी पालन करता है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारवाँ पर्यटन युवाओं, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित बाज़ार क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करेगा।

नोट :

मुख्यमंत्री ने 'नवसृजन एक परिचर्चा' के पोस्टर और पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में वेदिका फाउंडेशन एवं गुनजंस आयोजन के संयुक्त तत्त्वाधान में अगस्त माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम 'नवसृजन एक परिचर्चा' के पोस्टर और पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- वेदिका फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संचालिका गुंजन चौहान चंदेल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं एवं प्रयास पर चर्चा होगी।
- साथ ही कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादों को स्टॉल में प्रदर्शित एवं विक्रय किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचित पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका के संपादक उदय हरवंश हैं।

नोट :

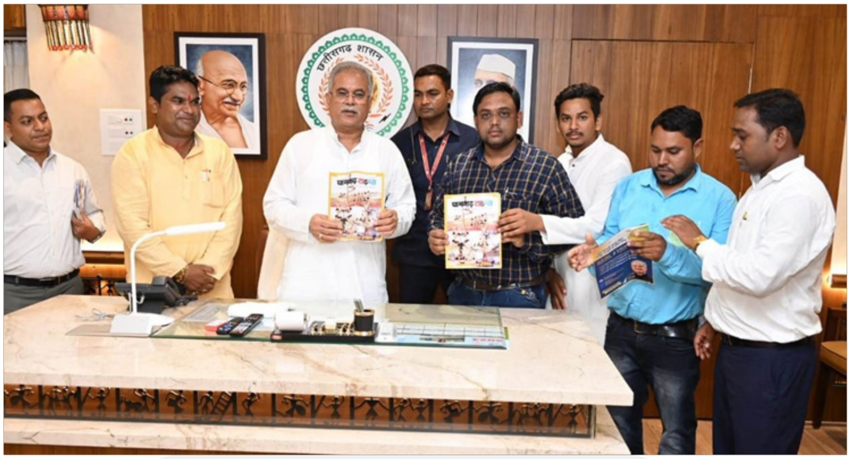

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये लगभग 1188.36 करोड़ रुपए की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य के युवाओं को बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगी।
- कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार विभाग के संचालक अवनीश शरण तथा टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के प्रेसिडेंट पवन भगेरिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण से राज्य के युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से कहा कि गांव में छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किये गए हैं, जहाँ व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये ज़मीन, बिजली, पानी, शेड, प्रशिक्षण, वाई-फाई की सुविधा एवं बैंकिंग लिंकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।
- टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, उनमें शासकीय आई.टी.आई.-बैकुंठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी-बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पंडरिया, गुंडरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं।
- आईटीआई उन्नयन परियोजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विश्व स्तर के अत्याधुनिक निम्नलिखित 6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें एक वर्षीय ट्रेड में आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्निशियन, मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन शामिल हैं।

नोट :

- इसी प्रकार दो वर्षीय ट्रेड में एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एंड वर्चुअल वेरिफायर (मैकेनिकल), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेड शामिल हैं।
- टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा चयनित प्रत्येक आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक आईटीआई में प्रारंभ में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एवं उसके सहयोगी उद्योग सहयोग प्रदान करेंगे। योजना से प्रतिवर्ष लगभग 10 हज़ार युवा लाभान्वित होंगे।
- गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केंद्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 01 अक्तूबर, 2022 को एमओयू किया गया था। इसकी अगली कड़ी के रूप में आज टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु एमओयू किया गया।

नोट :

रायपुर बनेगा पपीता उत्पादक ज़िला : एक उत्पाद-एक ज़िला योजना में रायपुर शामिल

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायपुर ज़िले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिये जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 'एक उत्पाद-एक ज़िला योजना' के तहत रायपुर ज़िले का चयन पपीते की खेती के लिये हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- यह जानकारी 21 जुलाई को एक उत्पाद-एक ज़िला के तहत पपीता उत्पादन से पोषण की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी गई। ज़िला पंचायत रायपुर के सीईओ अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन लाभांडी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।
- किसानों को उन्नत और रोग-प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के पौधे उपलब्ध हो सके, इसके लिये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बैंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीते का पौधा रायपुर लाया गया है। इसकी मदद से नर्सरी तैयार कर किसानों को रोपण के लिये अर्का प्रभात पौधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
- पपीते की नई प्रजाति अर्का प्रभात की विशेषता यह है कि यह स्पॉट वायरस रसिस्टेंट है। इसमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण पौधा रोग-रहित रहता है।
- कार्यशाला में किसानों को पपीते की खेती के लिये प्रोत्साहित करते हुए उप-संचालक उद्यानिकी कैलाश सिंह पैकरा ने कहा कि इसकी खेती के लिये शासन द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि पपीता एक पौष्टिक फल है। इसकी पत्ती भी उपयोगी है। पपीते के स्वस्थ पौधे उद्यानिकी रोपणियों एवं कृषि केंद्रों पर भी उपलब्ध है। इसकी खेती के लिये विभाग के अधिकारियों एवं प्रक्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा किसानों को जानकारी दी जा रही है।
- महाप्रबंधक, ज़िला व्यापार उद्योग अमेय त्रिपाठी ने किसानों को पपीते की मार्केटिंग, कोल स्टोरेज में रखरखाव और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान इसका लाभ उठाकर अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं।
- वैज्ञानिक डॉ. नीरज मिश्रा ने किसानों को बताया गया कि पपीता पौष्टिकता में सबसे अधिक है और इस फल से अनेक प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे जैम, जैली, कतरी, कैंडी आदि। इसके जूस एवं नेक्टर की भी अधिक डिमांड है। पपीते का पाउडर भी बनाया जा सकता है। पपीते का उत्पादन कर मंडी में बेचने के साथ ही किसान इसके प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान दें तो अधिक लाभ कमा सकते हैं।
- वैज्ञानिक मनोज कुमार साहू ने बताया कि पपीते की खेती को वायरस एवं बग्स से बचाने के लिये नीम के तेल के साथ शैंपू घोलकर छिड़काव किया जाना चाहिये। पपीते के पेड़ के आस-पास गेंदा फूल का पौधा लगाकर पपीते के पौधे को रोग से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

नोट :

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़-2023

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा जनजागरूकता में सहभागिता हेतु अनेक फिल्म निर्माताओं तथा नागरिकों के अनुरोध पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में पंजीकरण तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2023 से बढ़ाकर 10 अगस्त, 2023 तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2023 से बढ़ाकर 12 अगस्त, 2023 की गई है।
- उल्लेखनीय है कि इस महत्त्वपूर्ण आयोजन में अब तक देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा से कुल 64 तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के 80 प्रतिभागियों के पंजीकरण हुए हैं।
- फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री, प्रयोगात्मक, कथात्मक, काल्पनिक, गैर-काल्पनिक या एनीमेशन हो सकती है। मूल फिल्म यथासंभव उच्चतम गुणवत्ता (1920×1080 या उससे ऊपर) की सड़क सुरक्षा थीम पर आधारित होनी चाहिये।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ में भाग लेने के लिये कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और आयोजक टीम से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा। प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये। एक प्रतिभागी के लिये अधिकतम तीन प्रविष्टियों की पात्रता है। फिल्म की कुल अवधि क्रेडिट सहित (फ्रंट और एंड) अधिकतम 140 सेकंड (2.20 मिनट) हो सकती है।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ 2023 में दो श्रेणियों में प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाएगी। इनमें (1) छत्तीसगढ़ी भाषा (छत्तीसगढ़ी, गोड़ी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुड़ख, सदरी, बैगानी, कमारी, औरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोड़ी आदि) और (2) अन्य भारतीय भाषा, सभी प्रविष्टियों के लिये हिन्दी में उपशीर्षक अनिवार्य है।
- प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में प्रवेशकर्त्ताओं की मूल रचना होनी चाहिये एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। प्रतियोगी इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने अपनी लघु फिल्मों में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और छवियों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं।
- किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अश्लील/वयस्क फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ को अधिकार होगा कि महोत्सव के प्रचार उद्देश्यों के लिये प्रविष्टियों (प्रेषित चयनित/नामांकित फिल्में) एवं फिल्म की सामग्री का उपयोग छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा सकेगा और प्रत्येक फिल्म की प्रतियों को अपने महोत्सव पुस्तकालय के हिस्से के रूप में रखा जा सकेगा।
- सभी प्रविष्टियाँ चाहे पुरस्कृत हों या नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक हित के बिना सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिये उपयोग की जा सकती है। एक बार चयनित और अंतिम स्क्रीनिंग के लिये प्रस्तुत की गई फिल्मों को महोत्सव समाप्त होने तक किसी भी परिस्थिति में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रवेश के साथ फिल्म का एक डिजिटल पोस्टर (सोशल मीडिया क्रिएटिव) संलग्न करना होगा। जमा की गई सामग्री आवेदक को वापस नहीं की जाएगी। (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) के चयन के लिये जूरी का मूल्यांकन अंतिम होगा। कोई भी प्रतियोगी जूरी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा।
- किसी भी फिल्म निर्माता, संस्था, संगठन को 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़' नाम के उपयोग की अनुमति नहीं है। आयोजन समिति की अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिये 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़' नाम एवं आयोजन के प्रतीक चिन्ह के उपयोग की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नोट :

स्टार्ट-अप, स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु स्थापित होंगे 35 इंक्यूबेशन सेंटर

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि शिक्षा गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये अब तक कुल 35 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिये कार्य-योजना बनाई गई है।

प्रमुख बिंदु

- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और युवाओं को रोज़गारोन्मुखी बनाने के लिये यह निर्णय लिया गया था कि सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाए।
- उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सात विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किये जा रहे हैं, 9 विश्वविद्यालय एवं 19 स्वशासी महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
- उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में I-Technology Based Incubator के लिये 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
- प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के.सी. गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2020-21 की एआईएसएचई रिपोर्ट के अनुसार सकल पंजीयन अनुपात (जी.ई.आर.) 27.1 प्रतिशत है, जो देश के जी.ई.आर. 27.3 के निकट है।
- एआईएसएचई पोर्टल पर वर्ष 2021-22 के लिये प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं स्टैंड एलोन संस्थानों का कुल 88 प्रतिशत डाटा प्रविष्टि का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिये डाटा प्रविष्टि का कार्य सितंबर-2023 से प्रारंभ किया जाएगा।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक संभाग में एक शासकीय महाविद्यालय का उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 4 संभाग इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं ग्वालियर में उत्कृष्टता महाविद्यालय तथा 10 जिले मुरैना, दतिया, पन्ना, सतना, अनूपपुर, खंडवा, सीहोर, बैतूल, बालाघाट एवं नीमच में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना के लिये अतिरिक्त बजट के लिये प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को राजधानी रायपुर में कृषि विभाग समर्थित, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और सोसाएटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिये मंच प्रदान करना था, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सरकारी पहल और पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया।
- साथ ही महिलाओं के लिये आजीविका के विकास और संबंधित एफपीओ की स्थिरता के लिये एक सक्षम वातावरण विकसित करने के लिये एक रणनीति पर विचार-विमर्श करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था।
- वक्ताओं और विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र में अमूल्य अनुभव को साझा किया। इन सभी हितधारकों को एक साथ आने और प्रासंगिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने और नीतियों के लिये अन्य सुझावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।
- एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) के तहत पूरे भारत में व्यक्तियों की आजीविका में सुधार के लिये कई पहल की है। एचडीएफसी बैंक, विशेष रूप से ऑन-फार्म, ऑफ-फार्म और गैर-फार्म के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आजीविका हस्तक्षेप के सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) का उद्देश्य 5 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ाना और 2 लाख से अधिक युवाओं, महिलाओं और किसानों के कौशल का विकास करना है। एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) ने राज्य में स्थानीय आर्थिक सक्रियता को भी गांवों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों के माध्यम से बढ़ावा दिया है।
- सम्मेलन में एफपीओ के निदेशकों, सार्वजनिक और निजी हितधारकों और विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों ने भाग लिया। इसमें राज्य के भीतर और बाहर के सफल एफपीओ के अनुभव को साझा करना भी शामिल था।

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव ज़िले का तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ज़िला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिये जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव ज़िले को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिये 'चैंपियन ऑफ चेंज' के तौर पर ज़िले की सराहना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में ज़िले में उत्कृष्ट कार्य हुये हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिकेटर्स जैसे माइक्रो इरिगेशन से रकबे में वृद्धि, मनरेगा अंतर्गत तैयार जल स्रोत, पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर राजनांदगांव ज़िले ने यह सफलता हासिल की है।
- उल्लेखनीय है कि मई 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग में देश के सबसे विकसित आकांक्षी ज़िलों में राजनांदगांव ज़िले ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

- राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं जैसे- सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं से ज़िले में कृषि एवं नवीनतम तकनीक से किसानों में खुशहाली आई है। वहीं जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी नवाचारी पहल से अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं।

हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई व्यावसायिक प्रशिक्षण का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में होगा लागू

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किये गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटिग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिये दिशानिर्देश तैयार करेगी।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र, जो साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिये स्कूलों एवं आईटीआई के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।

नोट :

- प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत आई.टी.आई. की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के बारहवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है।
- वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों एवं आईटीआई में प्रारंभ की गई है, जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत उद्यमिता कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने मोर बिजली ऐप के नए वर्ज़न 2.0 को किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- 29 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान 'मोर बिजली ऐप 2.0' का शुभारंभ किया। मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से अब उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएँ मिलेंगी।

प्रमुख बिंदु

- मोर बिजली ऐप के पहले वर्ज़न को बिजली उपभोक्ताओं की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के कारण ही नागरिक सेवाओं को विस्तार देते हुए ऐप के दूसरे वर्ज़न को तैयार किया गया है।
- नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिये छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने छत्तीसगढ़ी बोली को एसएमएस की भाषा के रूप में चुना है, उन्हें मासिक बिजली बिल, बिल भुगतान, बिल भुगतान रिमाइंडर और बिल भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ी में भेजी जाएगी। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए ऐप में हमारी सरकार द्वारा चलायी जा रही 'बिजली बिल हाफ योजना' अंतर्गत उपभोक्ता को योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक बिजली बिल में प्राप्त छूट की राशि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही उपभोक्ता छूट की राशि का प्रमाण-पत्र भी डाउनलोड कर पाएंगे।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च किये गए मोर बिजली ऐप 2.0 में 36 प्रकार की उपभोक्ता सेवाएँ प्राप्त होंगी, जिसमें बिल की जानकारी, गणना, दरें, बिल भुगतान सुविधाएँ, जैसे- ऑनलाइन भुगतान, नजदीकी भुगतान केंद्र, पिछले दो वर्षों का बिल भुगतान विवरण, बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की जानकारी, विद्युत आपूर्ति तथा बिल से जुड़ी शिकायतें, जैसे- बिजली बंद, बिल संबंधी शिकायतें, आपातकालीन तथा विद्युत अवरोध, ट्रांसफार्मर की खराबी आदि की सुविधाएँ मिलेंगी।
- इसके साथ ही नए बिजली कनेक्शन, नाम परिवर्तन, टैरिफ परिवर्तन, लोड बढ़ाने-घटाने, मीटर शिफ्टिंग जैसी सुविधाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उपभोक्ता अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे।
- उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल, जैसे- मोबाइल नंबर जोड़ने-बदलने, ई-मेल आईडी के साथी बिजली कनेक्शन प्रोफाइल ऐप के माध्यम से बना पाएंगे। एसएमएस और मोबाइल ऐप की भाषा का चुनाव भी आसानी से हो सकेगा।
- छत्तीसगढ़ के 'भुईयां' मोबाइल ऐप के बाद सिर्फ 'मोर बिजली ऐप' को ही 10 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। 6 अक्तूबर, 2020 को लॉन्च हुए मोर बिजली ऐप के पहले वर्ज़न को 13 लाख 25 हज़ार से अधिक उपभोक्ता डाउनलोड कर उपयोग में ला रहे हैं।
- गूगल प्ले स्टोर में नि:शुल्क उपलब्ध इस मोबाइल ऐप को 36 हज़ार 700 से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा 5 में से 4.4 की रेटिंग दी गई है। राज्य में मोर बिजली के ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, यही इसकी सफलता का परिणाम है।
- छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल की जानकारी, बिजली बिल का भुगतान और बिजली बंद होने की शिकायत के लिये मोर बिजली ऐप का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बिजली बंद होने की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें मोर बिजली ऐप के माध्यम से प्राप्त हो रही है। शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण भी 70 प्रतिशत से बढ़कर अब 94 प्रतिशत हो गया है।